Vol 6 Issue 8 September 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

ISSN: 2230-7850 Impact Factor :4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 8 | September - 2016

Indian Streams Research Journal

उत्तरांचल (उत्तराखंड) की शिक्षा व्यवस्थाः ऐतिहासिक

डॉ. जयश्री थपलियाल

प्रास्ताविक :–

उत्तराखंड भारत के मध्य हिमालयी क्षेत्र का महत्वपूर्ण राज्य है। 9 नवम्बर, 2000 को गठित इस प्रदेश का नाम बदलकर उत्तरांचल रखा गया कुछ समय बाद इसका नाम बदल कर उत्तराखंड रखा गया। उत्तराखंड की अपनी अनुठी संस्कृति है। विशेष नैसर्गिक सौंदर्य और भूगोल आदि के कारण यह राज्य देश–दुनिया में प्रसिद्ध है।

उत्तराखंड राज्य शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है यहाँ राजकाज की भाषा हिन्दी है किंतु स्थानीय भाषाएं गढवाली, कुमाउंनी और जौनसारी हैं। साहित्यिक दृष्टि से ये भाषाएं समृद्ध हैं। सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के साथ ही कॉन्वेंट तथा पब्लिक स्कूलों तथा निजी विश्वविद्यालयों ने यहाँ के शैक्षिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। उत्तराखंड जो कुछ वर्ष पूर्व तक उत्तरप्रदेश का एक अंग था और उसी के द्वारा शासित था भारतीय संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा हैं। यदि इसकी भौगोलिक, आर्थिक,सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक स्थिति की तुलना अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक पिछड़ा हुआ नहीं हैं। इस प्रदेश की भाषा हिन्दी हैं किन्तु यहाँ अन्य भाषाएं भी बोली जाती है यहाँ सरकारी शिक्षण संस्थाओ की अपेक्षा गैर–सरकारी शिक्षण संस्थाओं का काफी योगदान है।[1]

उत्तरप्रदेश के अन्तर्गत रहते हुए शिक्षा संचालन का मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में था व इसका एक कार्यालय लखनऊ में भी हैं शिक्षा संचालन की सहायता के लिए अन्य पदाधिकारी भी नियुक्त किये जाते थे । शैक्षिक दृष्टि से

उत्तर प्रदेश को निम्न 11 मण्डलो में बाँटा गया था – (1) आगरा (2) कुमाऊँ (3) पौंडी (4) बरेली (5) इलाहाबाद (6) वाराणसी (7) लखनऊ (8) गोरखपुर (9) मेरठ (10) झाँसी (11) फैजाबाद । इसके प्रमुख शिक्षा–अधिकारी उप–शिक्षा निदेशक होते थे। नैनीताल मण्डल जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन होता था। राज्य के आठ जिलों में–आगरा, मेरठ, लखनऊ,बरेली इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर व नैनीताल में जिला विद्यालय निरीक्षक की सहायता के लिए एक सम्बद्ध विद्यालय निरीक्षण व प्रत्येक जिले में जिला–विद्यालय निरीक्षण की सहायता के लिए उपविद्यालय निरीक्षक होते थे।[2]

उत्तरप्रदेश के बावन जिलों में एक–एक जिला विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति होती थी यह जिले में शिक्षा–विभाग का सबसे बडा अधिकारी होता था। इनके कर्तव्य इस प्रकार थे जैसे–प्राइमरी शिक्षा कि प्रगति जिले के माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण,ग्रान्ट बिलों को पास करना,उच्च माध्यमिक विद्याालय को मान्यता प्रदान करना,जूनियर हाईस्कूल परीक्षा संचालित करना,विद्यालयों में धन के उपयोग पर ध्यान व विद्यालयों का अनुशासन देखना। उत्तरप्रदेश की शिक्षा का संगठन पूर्व प्राथमिक शिक्षा,माध्यमिक शिक्षा एंव विश्वविद्यालय शिक्षा में बँटा हुआ है।

उत्तराखंड की धरती ऋषि–मुनियों की तपस्थली के साथ विद्वान मनीषियों की सुमन स्थली भी रही है। इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार–प्रसार में धर्म–ध्वजाधारियों नें इस क्षेत्र की सांस्कृतिक महत्ता को समझकर यहाँ मठ–पीठ,आश्रम आदि स्थापित किये। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड प्राचीन काल से ही उन्नत दशा में था। आश्रमों व गुरूकुलों में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। संस्कृत भाषा सीखने के लिए देश के अन्य भागों से लोग यहाँ आते थे। प्राचीन काल में उत्तराखंड में आश्रम प्रथा प्रचलित थी। लोक–मान्यता हैं कि मलिनी नदी के तट पर महर्षि कण्व का आश्रम था जहाँ हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करतें थे। यहाँ के लोग संस्कृत भाषा में अत्यन्त प्रवीण थे।[3]

प्राचीन समय में बालकों की शिक्षा घर से ही प्रारम्भ हुआ करती थी जैसे कि देश के बाकी हिस्सें में होती थी। शिक्षा के केन्द्र आश्रम व गुरूकुल हुआ करतें थे, जहाँ छात्र शिक्षा प्राप्त करते थें। गुरूओं की देख–रेख में उपनयन संस्कार के पश्चात शिक्षा प्रारम्भ की जाती थी। बालक को गायत्री उपदेश देकर शिक्षा आरम्भ की जाती थी। प्राचीन काल में गुरू का स्थान राजा, माता–पिता एवं देवता से कम नहीं था। वे गुरू की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थें। गुरू की सेवा करना अपना परम धर्म समझतें थे। गुरू अपने विद्यार्थियों के चरित्र–निर्माण का सदैव ध्यान रखता था। जब तक छात्र विद्या प्राप्त करता था तब तक गुरू

उससे किसी प्रकार का शुल्क स्वीकार नहीं करता था।

शिक्षा समाप्त होने पर छात्रों या उनके माता पिता द्वारा जो भी दक्षिणा दी जाती थी वे खुशी से स्वीकार कर लेते थे। छात्र अपने गुरू का घर का काम–काज करते थे। इस दौरान छात्र व गुरूओं के बीच ऐसे सम्बन्ध कायम हो जातें थे जो इज्जत,वफादारी जैसी खुशियों का बढावा देती थी। आश्रम में इन छात्रों के संरक्षण की उम्र पन्द्रह से बीस साल के बीच होती थी पर धीरे–धीरे यह समय के साथ बदलती गई। प्राचीन काल में शिक्षा पर राज्य सरकार अथवा किसी राजनैतिक दल का नियन्त्रण नहीं था। वेदों की शिक्षा के अतिरिक्त और भी अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। (जैसे–इतिहास,पुराण,व्याकरण,अर्थशास्त्र,गणित, धर्मशास्त्र,शस्त्रविद्या,दर्शनशास्त्र,कानून,औषधि–विज्ञान) आदि विषयों की भी शिक्षा प्रदान कि जाती थी,[4] शिक्षण विधि मौखिक थी।

छात्रों को गुरू द्वारा बताई गई सभी बातों का ध्यान व मन लगाकर सुनना होता था। मध्यकाल में आश्रमों नें पाठशालाओं का रूप ले लिया था जो कि मन्दिरों से जुडी हुई थी।[5]

इस समय संस्कृत, व्याकरण, ज्योतिष, गणित आदि विषयों के अलावा हिन्दू धर्मग्रन्थों को भी पढ़ाया जाने लगा।[6] ये शिक्षा के निजी संस्थान थे, इन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती थी। उत्तराखंड में शिक्षा का प्रारम्भ बसन्त पंचमी के दिन से कराया जाता था। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती थी व बालक को विद्यारम्भ या अक्षरारम्भ कराया जाता था । इस दिन बच्चे का कर्ण–छेदन भी किया जाता था। घर के बडें या कुलगुरू द्वारा पूजा–वन्दना के उपरान्त बालक को अक्षरारम्भ कराया जाता था । कान–नाक छेदन से पहलें छेदे जाने वाले स्थान पर राख मली जाती थी। चांदी के गर्म तार से छेद दिया जाता था। जब बच्चा दर्द से चिल्लाता था तो उसके मुँह में लड्डू या गुड़ डाल दिया जाता था और यहीं से बालक को जीवन–दर्शन का पहला अध्याय पढाया जाता था। शिशु की शिक्षा का श्रीगणेश ''ओम नमः सिद्धम'' के शब्द से होता था। पाटे, पट्रें को साफ करके उसके ऊपर अच्छे स्थान की लाल मिट्टी पीस कर बिछा दी जाती थी।

पूजा के पश्चात रोली–अक्षत चढाकर मंगलकारी प्रतीक बनाकर शिशु की अंगुली पकडकर मिट्टी में ''ओम नमः सिद्धम'' लिखवाया जाता था। इसके पश्चात बालक को ओ, ना, मा, सी, धंग, अ, आ, इ, ई, अं, अः आदि अक्षर लिखना–पढना शुरू कराया जाता था। जब बालक को अक्षरों का ज्ञान होने लगा, तब उसे लिखने के लिए तख्ती व कलम दी जाती थी। यह कलम पहाड़ में रिंगाल नामक पौधे से बनाई जाती थी। पहाडों में तख्ती काली हाती थी उसे उल्टे तवे कि कालिख से काला कर के पोता जाता था।[7]

उन्नीसवीं शती से पूर्व शिक्षा के प्रचार के विकास के लिएं किये गये किसी विशेष कार्य का उल्लेख नहीं मिलता है। 1823 में उत्तराखंड में इंग्लैण्ड की भांति शिक्षा की प्राप्ति के लिए कोई विद्यालय नहीं था। तीन कमिश्नरों – बैटन, रैमजे और ट्रेल के प्रयासों से उत्तराखंड में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। 1864 में बैटन ने अपनी भूव्यवस्था में ''शिक्षा देय'' लगाकर आधारिक विद्यालयों की स्थापना की थी। सरकारी विद्यालय न होने पर 1840 से पूर्व जिले में कुछ ब्राहमणों द्वारा विद्यालयों कि स्थापना की गई थी, जिसमें हिन्दी, संस्कृत, ज्योतिष, वैद्यक, कर्मकाण्ड आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

संम्पन्न ब्राहमणों के पुत्र बनारस जा कर भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करतें थे। सरकार ने पहला विद्यालय श्रीनगर में स्थापित किया जिस पर पाँच रूपयें मासिक खर्चा होता था। यह राशि लावारिस सम्पत्ति के फंण्ड से दी जाती थी। कलकत्ता में एजुकेशन कमेटी की अनुमति लेकर कमिश्नर ने चौदह रूपये मासिक व्यय पर गढ़वाल में और बीस रूपये मासिक व्यय पर कुमाऊँ में विद्यालय स्थापित किये।[8]

1850 तक सरकार शिक्षा उपलब्ध कराना अपना कर्तव्य नहीं समझती थी। सरकारी सहयोग के अभाव में मिशनरियों और स्थानीय लोगों ने अनौपचारीक शिक्षा प्रारम्भ की । उस समय उत्तराखंड में करीब एक सौ इक्कीस हिन्दी व संस्कृत विद्यालय थे। इन विद्यालयों मे से चौवन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी व सड़सठ ऐसे विद्यालय थे जिनकी मासिक आय साढें नौ रूपयें थी। इन विद्यालयों में छात्र संख्या पाँच सौ बाईस थी, जिनमें अस्सी प्रतिशत ब्राह्मण छात्र थे। एक उर्दू का विद्यालय भी था[9] जिसमें दस छात्र पढते थे।

1884 में विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की आयु कम से कम छः–सात वर्ष व अधिक से अधिक सोलह वर्ष तक थी। बालक नियमित रूप से रोज विद्यालय नहीं पहुँचतें थे, क्योकि उन्हे अपने घर व खेतों के कार्य भी करने होते थे। 1884 के बाद धीरे–धीरे नये विद्यालय खोलने के लिए आवेदन पत्र आ रहे थे। माता–पिता भी चाहने लगे थे कि उनके बच्चे हिन्दी व अंग्रेजी पढें। 1884 तक शिक्षा के प्रसार के कारण जनता पर अब तक चलें आये ब्राहमणों के प्रभुत्व में कमी आने लगी थी। उत्तराखंड के विद्यालयों का निरीक्षण एक हिन्दुस्तानी निरीक्षक व उसके आधीन उप–निरीक्षकों द्वारा किया जाता था। सभी बालक–बालिकांओं के लिए विद्यालय की स्थापना करने में सरकार सक्षम नहीं थी। जो लोग अमीर थे वे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध स्वंय कर लेते थे। कुमाऊँ में अब तक अन्य जिलों की अपेक्षा लिखने–पढने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक हो गया था।[10]

1864 व उसके पश्चात् जिले में तैंतालीस विद्यालय खुले जिनमें हल्काबन्दी विद्यालयों में लोअर प्राइमरी तक व तहसीली विद्यालयों में प्राइमरी तक की शिक्षा दी जाती थी शैक्षिको का वेतन बहुत कम था व यहाँ शैक्षिक वातावरण की कमी थी। पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों की एक प्रमुख समस्या अनुपस्थिति की थी।[11]

इन क्षेत्रों में अभिभावक जीविकोपार्जन के लिए कई महिनों तक घर से बाहर रहतें थे। फलतः धर में खेतीबाड़ी तथा सामाजिक कार्यो का दायित्व छात्रों को वहन करना पडता है। यही हाल शिक्षक वर्ग का भी था। अनेक विद्यालय बिना भवन के व अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों के अपने भवन थे। किन्तु वे भी अच्छी दशा में नहीं थे। वर्षा ऋतु में अनेक विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित हो जाता था। यही हाल जूनियर स्कूल व हाईस्कूलों का था। छात्रावास की व्यवस्था बहुत ही कम विद्यालयों में थी। अनेक विद्यालयों में तो शिक्षण–सामग्री, बच्चों के बैठने के लिए टाट–पट्टी, लिखने के लिए श्यामपट्ट और चाक भी उपलब्ध नही थे।

उत्तराखंड में प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल परीक्षा के सम्पादन का पूरा दायित्व प्रति उप– विद्यालय निरीक्षकों पर था। प्राथमिक विद्यालयों की पाँचवीं श्रेणी की परीक्षा के वे सर्वे–सर्वा होते थे। वे अपनी सुविधानुसार दस–पंन्द्रह प्राथमिक विद्यालयों के परीक्षार्थियों की एक स्थान पर परीक्षा लेते थे, और समस्त विषयो की परीक्षा दो–तीन घंटे के अंन्दर समाप्त हो जाती थी। कुछ विषयों में बिना परीक्षा लिए ही अंक दे दिये जातें थे। कई स्थानो पर नकल करने की पूरी छूट होती थी, इससे शिक्षा के स्तर पर बुरा प्रभाव पडता था व बहुत से अयोग्य छात्र भी उत्तीर्ण कर दिये जाते थे।

किसी भी देश या राज्य की शिक्षा–व्यवस्था वहाँ के राजनैतिक , भौगोलिक तथा जैविक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। पाठ्यमक्रम भी शिक्षा–व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है यहाँ का अधिकांश विद्यार्थी वर्ग स्कूली शिक्षा के बाद ही समाज में लौट आता है व जीवनयापन के साधन खोजने लगता है। इसलिए पाठ्यक्रम को समय–समय पर नवीन व समयोपयोगी होना चाहिए। उत्तराखंड में चाहें हाईस्कूल हो, माध्यमिक स्तर की संस्था हों या महाविद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान कराने वाला पाठयक्रम है।

उत्तराखंड क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है । प्राकृतिक सम्पदा के भण्डार और सुषमा के बीच भी यहाँ का जीवन संघर्षमय और कठोर है। इसके लिए बहुत कुछ सीमा तक यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। दूरगामी पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण आने–जाने के साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं है। देश के अन्य भागों में जिस प्रकार शिक्षा विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति हुई उस गति से इस क्षेत्र में कुछ भी न हो पाया। वैसे आश्रम गुरूकुलों की परम्परा उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही विद्यमान थी व ज्योतिष विद्या का तो गढ़ रहा है। समय के बढते चरणो नें धीरे–धीरे इस क्षेत्र के लिए भी आधुनिक शिक्षा के द्वार खोले। विदेशी मिशनरियों ने यहाँ अनेक विद्यालय खोले भले ही उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो उत्तराखंड में विद्यालय जिस क्रम से खुले, उसी क्रम से समस्या भी सामने आई पिछडा हुआ क्षेत्र के कारण आर्थिक समस्या सबसे बडी बाधा थी। आर्थिक कठिनाई के कारण यहाँ विद्यालयों के लिए आवश्यक इमारतें, साज–सामान तथा अन्य उपकरण नहीं जुट पातें। खेल के मैदान, पुस्तकालय या विज्ञान की प्रयोगशाला की व्यवस्था, फर्नीचर से सम्बन्धित कठिनाई आदि ने शिक्षा की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

यहाँ का जीवन कृषि प्रधान है इसलिए यहाँ के पिछड़े हुऐ क्षेत्रों में बच्चों को पढाना–लिखाना आवश्यक नहीं समझा जाता। साथ ही विद्यालयों की दूरी, यातायात के साधन की कमी, पुस्तकों व फीस की अदायगी न कर सकने कि स्थिति भी बच्चों को विद्यालय भेजने में बाधक है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यालय चार–पाँच मील दूर उबड़–खाबड़ व कंटीले रास्तें पार कर के जाना पडता है। हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज की संख्या बहुत कम थी। और जो थे वे भी दूर स्थानों पर थे। विद्यालयों की स्थिति ऐसी थी कि उठने–बैठने की आवश्यक सुविधाएं भी नहीं थी। पढ़ाने के लिए प्रायः विद्यालय मे एक अध्यापक से अधिक नही होता था। कभी–कभी तो ऐसी स्थिति भी आ जाती थी कि एक ही अध्यापक महिनों विद्यालय के सारे छात्रों के लिए उपलब्ध होता था। पाठशाला भवनों की स्थिति भी काफी खराब थी।

15 अगस्त 1947 के बाद भारत सरकार ने देश का दायित्व सम्भाला व राज्य सरकारों को शिक्षा का भार सौंपा तथा केन्द्र में शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया व समय–समय पर आयोग व समितियाँ नियुक्त कीं।

1948 में भारत सरकार ने अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा–व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से 1948 में ''विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग'' की स्थापना की इस आयोग के अध्यक्ष डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग को राधाकृष्णन के नाम से भी जाना जाता है।[12]

इस आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य थे–भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना और उन सुधारों एवं विस्तारों के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना जो देश की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं के लिए जरूरी है।[13]

ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की ओर जनता एवं सरकार का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित करने का श्रेय इसी ''कमींशन'' को प्राप्त है। 1952 में ''मुदालियर आयोग'' कि स्थापना की गई। इस आयोग के अध्यक्ष डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इस आयोग की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने हेतु की गई थी। इस आयोग को ''माध्यमिक शिक्षा आयोग'' के नाम से भी पुकारा जाता है। इस आयोग ने शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, छात्रों की व्यक्तिगत अभिरूचि, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, विद्यालयों की योजना छात्रों के व्यवसायों का चयन, कृषि–शिक्षा, परीक्षा–प्रणाली, अध्यापक–प्रशिक्षण व शिक्षको की स्थिति में सुधार पर बल दिया। यदि आयोग के अधिकाशं सुझावों को क्रियान्वित कर दिया जाता तो माध्यमिक शिक्षा इस देश में निश्चित रूप में एक स्वस्थ आधार पर प्रतिष्ठित हो जाती व सम्पूर्ण देश की प्रगति सम्भव हो पाती।[14]

1964 में ''विश्वविद्यालय–अनुदान–आयोग'' के प्रधान प्रोफेसर डी0एस0 कोठारी की अध्यक्षता में कठोरी आयोग की स्थापना हुई। भारत सरकार देश की शिक्षा–व्यवस्था की जांच कराके एक शिक्षा योजना तैयार कराना चाहती थी जिसके लिए सरकार नें शिक्षा आयोग की स्थापना की। इसमें एक हजार व्यक्तियों ने भाग लिया व कई दिनो तक देश की यात्रा की। आयोग ने दो वर्ष पश्चात अपनी रिपोर्ट दी व बीस वर्ष के भावी राष्ट्रीय शिक्षा–क्रम की योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया।[15]

आयोग ने कई अच्छें सुझाव दिये जैसे–शिक्षकों की वेतन–दरों में वृद्धि, पैंसठ वर्ष कार्य करने की अनुमति, विज्ञान पर आधारित शिक्षा व शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध आदि।

1947 में भारत स्वतन्त्र हुआ। दो विश्व–युद्धों, अंग्रेजों की शोषण नीति व देश के विभाजन ने राष्ट्र के समक्ष कई समस्याऐं पैदा कर दी थी। विश्व के अनेक देशों की तरह भारत ने भी अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र करने व एक निश्चित दिशा में अग्रसर करने के उद्देश्य से 1951 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की। अन्य विषयों के साथ–साथ इसमें शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। 1951 तक भारतीय शिक्षा की काफी खराब थी। देश में साक्षरता का प्रतिशत सत्रह दशमलव दो था। इसके अतिरिक्त प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा कि व्यवस्था का अनुपात बराबर था। विश्वविद्यालयों की शिक्षा इतनी विस्तृत थी कि बुनियादी शिक्षा उसका भार नहीं सम्भाल पा रही थी। उच्चशिक्षा को अधिक महत्व मिलने लगा था। टैक्निकल व व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं न मिलने के कारण छात्रों को साधारण शिक्षा प्राप्त करनी पडती थी। पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। शिक्षा क्षेत्र में योग्य अनुभवी शिक्षकों का अभाव था। सभी को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नही थी। छः से ग्यारह वर्षकी आयु के चालीस प्रतिशत, ग्यारह से सत्रह के दस, सत्रह से तेईस के नौ प्रतिशत व्यक्तियों को ही शिक्षा मिल पाती थी। नगर–ग्राम में शिक्षा सुविधाओं की असमानता थी व अध्यापकों की कमी थी।[16]

भारतीय शिक्षा को जनता के अनुकूल बनाने के लिए शिक्षा का पुनर्गठन करना जरूरी था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। 1956–61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो अभाव रह गये थे उन्ही को ध्यान में रखकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961–66 तक चली। तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा प्रसार के कार्यक्रम का विस्तार करना।

चौथी योजना 1969–74 तक चली। पिछली तीन योजनाओं में छात्रों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई पर व्यावसायिक व कृषि–शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया व बालिकाओं की शिक्षा काफी पिछड़ी हुई थी। देश के कुछ भागों में बालक–बालिकाओं दोनों की शिक्षा पिछडी हुई थी। इन दोषों को दूर करने के लिए चौथी योजना में प्रयास किये गये।

पाँचवी योजना 1974–79 तक चली। इस योजना में शिक्षा के सभी अंगो की ओर ध्यान दिया गया व उनकी व्यवस्था की गई, जैसे–शिक्षा व रोजगार, भाषा का विकास, पुस्तकों का प्रकाशन कला एवं संस्कृति, शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम व समस्याओं आदि पर विशेष बल दिया गया।

उत्तराखंड में स्वतंन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा की प्रगति की दिशा में शासन ने भी बहुत सहायता की है, विशेषकर उच्च शिक्षा तथा महाविद्यालयों की स्थापना में। लेकिन माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकांश भार आम जनता ने उठाया है। उत्तराखंड में स्वतंत्रता प्राप्ति सें पहले ब्रिटिश शासन में केवल पाँच जिलें थें– ब्रिटिश गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल (रियासत), नैनीताल, देहरादून, अल्मोडा। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तराखंड आठ जिलों में विभाजित हो गया। देहरादून, पौडी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल , चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ़, । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में टिहरी रियासत उत्तरप्रदेश में विलीन हुई।

उत्तराखंड की शिक्षा का निर्देशन प्रादेशिक सरकार द्वारा होता था। 1960 में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी इन तीन सींमान्त जिलों का निर्माण हुआ है व 1975 से देहरादून प्रशासनिक रूप से गढ़वाल मण्डल में मिला दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उतराखंड की शिक्षा को तीन भागो में बाँटा गया– प्राइमरी, माध्यमिक – (निम्नस्तर माध्यमिक,व उच्च/उच्चतर माध्यमिक) तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय, 1948 में जो नई सरकार आई उसने नई शिक्षा नीति बनाई, जिससें सारे जिलों में एक आन्दोलन सा चल गया। लोगो ने कई स्थानो पर प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की। सरकार ने स्कूलों की स्थापना व अध्यापकों की नियुक्ति की। सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी लागू किया, जिससें लोगों ने शिक्षा के प्रति अपनी रूचि दिखाई। पर अब भी गाँव की स्थिति खराब थी। लोग इस दशा में नहीं थे कि वे खेती–बाडी से हटकर अपने बच्चों को स्कूल में दखिला दिला सकें।[17] हरिजनों की स्थिति और भी खराब थी।

उतराखंड की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी जिसके कारण लोगों ने नौकरी के लिए बाहर जाना आरम्भ कर दिया। ऐसा कोई भी (गढ़वाली) बालक नहीं था जो अपने घर से शहर नहीं भाग रहा था। कुछ तो घर से निरक्षर गये, पर बाहर से पढ–लिखकर आये। उत्तराखंड के अधिकतर लोग पढने के लिए इलाहाबाद, बनारस, देहरादून व करॉची जाते थे।[18]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के काफी समय पश्चात भी उत्तराखंड की शिक्षा–व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं आया। प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा तो आम जनता को प्राप्त हो गई परन्तु उसके बाद आगे की शिक्षा जैसे– उच्चतर, माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सुविधाएं कठिन ही थीं। उत्तराखंड में सामान्य स्थिति वाला व्यक्ति अपने बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा तो कठिनाई सें दिला देता है पर उसके बाद की शिक्षा देने वाले विद्यालय इतने दूर हैं कि छात्रों का वहाँ तक पहुँचना कठिन है।

उत्तराखंड कि समस्त प्राथमिक पाठशालाओ में बेसिक पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होती थी। पढ़ाई के विषय इस प्रकार हैं– भाषा, गणित, सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान। इनके अतिरिक्त बागवानी, कताई–बुनाई, स्थानीय–शिल्प व आर्ट भी सिखाया जाता था। सारे उत्तराखंड में शिक्षा का माध्यम हिन्दी था। नगरपालिकाओं व नैनीताल जिले के देहाती क्षेत्र जसपुर की कुछ पाठशालाओं में उर्दू माध्यम द्वारा पढ़ाई का प्रबन्ध था। स्वतन्त्रता के पश्चात उत्तराखंड कि शिक्षा–व्यवस्था में कुछ सुधार आया। नगरपालिका की कुछ पाठशाला भवनों को छोडकर अन्य सभी भवन कक्ष पक्के थे। भवन में एक बरामदा, दो पढाई कक्ष तथा अध्यापक क्वार्टर व एक स्टोररूम था। स्कूलों में शिक्षण सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तकें, नक्शे, चार्ट, चित्र, श्यामपट्ट, सामान्य ज्ञान उपकरण, दस्तकारी का सामान, प्रत्येक पाठशाला में था। सभी शिक्षक प्रशिक्षित थे। तीन कक्षाओं (छः, सात, आठ कक्षा) वाले व जूनियर हाईस्कूलों में कम से कम पाँच अध्यापक कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्यापक भी थें उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय भाग में सभी छात्र संस्कृत का अध्ययन करते थे।[19]

माध्यमिक विद्यालयों में छः दस तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों में छः से बारह तक की कक्षायें साथ–साथ चलती हैं। ऐसे विद्यालय को ''पोस्ट बेसिक विद्यालय'' भी कहा जाता था। सरहदी जिलों को छोडकर शेष जिलों के विद्यालयों में छात्र संख्या पर्याप्त थी। देहरादून जिले के शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों की छात्र संख्या अधिक थी। इन सभी उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। कक्षा आठ की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्वयं लेते थे। कक्षा दस व बारह (हाईस्कूल व इण्टर) की वार्षिक परीक्षायें उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा–परिषद द्वारा ली जाती थीं। पौडीं गढवाल, चमोली, टिहरी व उत्तरकाशी के मुख्य प्रभागों, तीर्थ स्थानों व ऋषिकेश (देहरादून) में अनेक संस्कृत विद्यालय थे (जो आज भी विद्यमान है), जिनमें प्रथमा से लेकर मध्यमा, शास्त्री व आचार्य तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इनमें से अधिकांश विद्यालय राजकीय अनुदान पर चलते हैं तथा संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से परीक्षा दिलाते हैं। इन विद्यालयों का शिक्षा माध्यम हिन्दी व संस्कृत था।

वर्तमान में उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका हैं। यहाँ से कई प्रसिद्ध पत्रकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक राष्ट्रीय–अंर्न्तराष्ट्रीय फलक पर प्रसिद्व हैं। देहरादून और मसूरी में विभिन्न देशों से माध्यमिक स्तर तक कि शिक्षा ग्रहण करने के लिये छात्र यहाँ आते हैं। अलग राज्य बननें के बाद यहाँ कई विश्वविद्यालय स्थापित किये गये है। धार्मिक–आध्यात्मिक क्षेत्र में हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ विश्वपटल पर हिन्दु तीर्थों के रूप में प्रसिद्व होने के कारण देश–विदेश के अनेक लोग यहाँ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ की प्रकृति भी स्वमं में एक शिक्षक है। वह यहाँ के लोग को युगों–युगों से एक अनौखी एवं अलौकिक शिक्षा प्रदान करती आ रही है। नदी, पेड़, पर्वत, पत्थर के प्रति असीम आस्था रखने वाला यहाँ का जन इन्हे पूजता हुआ आ रहा है। प्रकृति के अत्यंत निकट होने के कारण यहाँ के निवासी प्रकृति से गूढ़ शिक्षा ग्रहण कर जीवन में उसका लाभ लेते हैं।

अभी भी उत्तराखंड का शैक्षिक भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अनेक बडें शिक्षण संस्थान यहाँ अभी भी स्थापित होते जा रहे हैं। यहाँ न केवल सामान्य, धार्मिक, आध्यात्मिक, विज्ञान, चिकित्सा संस्थान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि भारतीय सैन्य अकादमी (आई0एम0ए) देहरादून और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, मसूरी में सैन्य शिक्षा भी प्रदान की जाती है। मसूरी में लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशासनिक अधिकारियों को ''दीक्षित'' दिया जाता हैं।

Volume - 6 | Issue - 8 | September - 2016

सन्दर्भ सूची

1–राम बाबू गुप्त, भारतीय शिक्षा का इतिहास, पृ0 469 ।
2–एस0 पी0 सुखिया,विद्यालय प्रशासन एवं संगठन आगरा, पृ0 106 ।
3– के0 बी0 बुधौड़ी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंन्ट,सन् 1988, पृ0 33 ।
4– गजेटियर ऑफ इण्डिया,उत्तरप्रदेश – जिला पिथौरागढ, सन् 1979 ।
5– गजेटियर ऑफ इण्डिया, उत्तरप्रदेश जिला–चमोली, सन् 1979 ।
6– एल0 राइस, अपदिश टु द रिपोर्ट ऑफ इण्डिया एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882, पृ0 73 ।
7– चन्द्रशेखर बडोला, मध्य हिमालय में शिक्षा व शोध, सन् 1976, पृ0 3 ।
8– एटकिन्सन, हिमालयन डिस्ट्रिक्स, जि0 3, पृ0 543 ।
9– के0बी0 बुधौड़ी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलपमेन्ट, सन् 1988, पृ0 34 ।
10–एटकिन्सन,हिमालय डिस्ट्रिक्स,जि03, पृ0 545 ।
11– शिवप्रसाद डबराल,उत्तराखंड का इतिहास, भाग –7, पृ0 442–43 ।
12– तारा चन्द्र, डेवलपमेन्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इण्डिया,नई दिल्ली सन् 2004,पृ0 46 ।
13–रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन, पृ0 1 ।
14– भगवान दयाल,द डेवलपमेन्ट ऑफ मॉडर्न इण्डियन एजुकेशन, पृ0 329–30 ।
15– जी0एस0 वर्मा, आधुनिक भारतीय शिक्षा व समस्याएं,सन् 1996,पृ0 44 ।
16– प्रथम पंचवर्षीय योजना, पृ0 301–302 ।
17– भेंटवार्ता, विद्यादत्त नौटियाल,एडवोकेट विधायक मार्च 2002 ।
18– भेंटवार्ता, राधाकृष्ण कुकरेती, अखबार नया जमाना, देहरादून, जून 2002 ।
19– चन्द्रशेखर बडोला, मध्य हिमालय में शिक्षा व शोध, सन् 1976 पृ0 243 ।

डॉ. जयश्री थपलियाल

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org